IJAER/ March-April 2024/Volume-13/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का रोहिलखंड पर प्रभाव

Nadim Ahmad

Research Scholar M J P rohilkhand University Bareilly U. P

Dr. Anil Kumar

सार

इस अध्ययन पत्र में वर्ष 1857 तक रोहिलखंड पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभावों को जांच का विषय बनाया गया है। भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के परिणामस्वरूप क्षेत्र के आर्थिक वातावरण में काफी बदलाव आया। इन विकासों का कृषि, उद्योग, वाणिज्य और करों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। ऐतिहासिक स्रोतों और अकादमिक साहित्य की जांच करके, इस शोध का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने इस पूरे समय अवधि में रोहिलखंड के सामाजिक–आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया।

मुख्यशब्दरू *सामाजिक–आर्थिक स्थिति, जनसंख्या, साक्षरता, कृषि–जलवायु क्षेत्र*

परिचय

18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर विजय से आर्थिक नीतियों का एक नया युग आया, जिसका रोहिलखंड जैसे स्थानों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये नीतियां पूरे आर्थिक काल में लागू की गईं। इस लेख का उद्देश्य उन सटीक आर्थिक नीतियों की जांच करना है जो 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरण द्वारा लागू की गई थीं, साथ ही उन उपायों का उस समय तक रोहिलखंड की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था।

भू–राजस्व प्रणाली

रोहिलखंड में महालवाड़ी व्यवस्था के कार्यान्वयन का क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रणाली को लागू करने का ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का इरादा भूमि राजस्व निर्धारण को स्थायी तरीके से स्थापित करने के इरादे से था, जो बदले में औपनिवेशिक सरकार के धन इकट्ठा करने के प्रयासों को स्थिरता प्रदान करेगा। दूसरी ओर, भूमि–धारण पैटर्न, कृषि उत्पादन और किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर इसका जो प्रभाव पड़ा, वह बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं था। स्थायी निपटान के अनुसार, भूमि की आय भूमि के प्रत्येक व्यक्तिगत पार्सल के लिए पूर्व निर्धारित दर पर स्थापित की गई थी, और मालिक वे थे जो भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। जमींदार, जिन्हें जमींदारों के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार और किसान किसानों के बीच प्रमुख आय बिचौलिए थे, जिसके परिणामस्वरूप भूमि स्वामित्व के पैटर्न में पर्याप्त बदलाव आया। आय के संग्रह में उनकी भागीदारी के

परिणामस्वरूप, जमींदारों, जो या तो स्थानीय अभिजात वर्ग के सदस्य थे या अंग्रेजों के सहयोगी थे, ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण मात्रा में शक्ति और प्रभाव जमा कर लिया।

निश्चित भूमि कर निर्धारण लागू करने के परिणामस्वरूप किसान किसानों पर असंगत मात्रा में भार डाला गया था। किसान कभी–कभी जमींदारों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते थे। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में किसानों ने खुद को कर्ज और गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ पाया, उनके सामने अपनी कृषि आजीविका को बनाए रखते हुए अपनी भूमि आय जिम्मेदारियों को पूरा करने की चुनौती थी। यह दुर्दशा ब्रिटिशों द्वारा लागू की गई कठोर भूमि स्वामित्व प्रणालियों के कारण और भी बदतर हो गई थी। इन प्रणालियों ने किसानों के अधिकारों को सीमित कर दिया और भूस्वामियों के अधिकार को और अधिक मजबूत कर दिया। ब्रिटिश नियंत्रण के दौरान रोहिलखंड में जमींदारी प्रथा के उदय का क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जमींदार, अपने नए अर्जित धन और पद से उत्साहित होकर, अक्सर अपने किरायेदारों से ऊंची दरें वसूल कर, बिना कारण उन्हें बेदखल करके और अन्य प्रकार की जबरदस्ती करके उनका शोषण करते थे। नतीजतन, इसके परिणामस्वरूप किसान आबादी में व्यापक असंतोष और अशांति फैल गई, जिसने रोहिलखंड के कृषि समुदाय के भीतर सामाजिक तनाव और संघर्ष में योगदान दिया।

कृषि उत्पादकता के संदर्भ में, महालवाड़ी व्यवस्था कृषि क्षेत्र में विकास या नवाचार को प्रोत्साहित करने में विफल रहा। निश्चित भूमि राजस्व निर्धारण के साथ, जमींदारों या किसानों के लिए भूमि सुधार में निवेश करने या आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन था। परिणामस्वरूप, कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता स्थिर हो गई या गिरावट भी आई, जिससे ग्रामीण आबादी के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयाँ और बढ़ गईं। रोहिलखंड में महालवाड़ी व्यवस्था के कार्यान्वयन का भूमि स्वामित्व पैटर्न, कृषि उत्पादकता और किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। स्थिरता और समृद्धि प्रदान करने के बजाय, इस प्रणाली ने जमींदारी प्रथा को मजबूत किया, ग्रामीण गरीबी को कायम रखा और क्षेत्र में सामाजिक अशांति में योगदान दिया। यह औपनिवेशिक काल के दौरान रोहिलखंड की कृषि अर्थव्यवस्था और समाज पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है।

उद्देश्य

1. कृषि क्षेत्र के विकास के स्तर और विकासात्मक संकेतकों के इष्टतम संयोजन के आधार पर समग्र सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन ।

2. रोहिलखंड मैदान के विभिन्न जिलों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन का आकलन करना एक तुलनात्मक अध्ययन

कृषि का व्यावसायीकरण

ब्रिटिश शासन के तहत रोहिलखंड में नकदी फसल की खेती की ओर बदलाव ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया और इसका खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और स्थानीय

अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश नीतियों ने निर्यात बाजारों के लिए नील, अफीम और कपास जैसी नकदी फसलों की खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक एजेंडे द्वारा राजस्व निष्कर्षण को अधिकतम करने और ब्रिटिश उद्योगों में कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए प्रेरित था। परिणामस्वरूप, रोहिलखंड में भूमि के बड़े हिस्से को खाद्य फसलों से नकदी फसलों की ओर मोड़ दिया गया, जिससे कृषि पद्धतियों में बदलाव आया।

नकदी फसल की खेती को बढ़ावा देने से रोहिलखंड में पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर कई परिणाम हुए। किसान, जो पहले जीविका के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें उगाते थे, अब औपनिवेशिक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए नकदी फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर थे। इससे एक मोनोकल्चर प्रणाली का जन्म हुआ जिससे फसल विविधता कम हो गई और बाजार की कीमतों और पर्यावरणीय कारकों में उतार–चढ़ाव के प्रति कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता बढ़ गई। नकदी फसलों की ओर बदलाव का रोहिलखंड में खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूँकि वह भूमि जो पहले खाद्य फसल की खेती के लिए उपयोग की जाती थी, अब नकदी फसलों के लिए आवंटित की गई, आवश्यक खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया। इसका स्थानीय आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता और सामर्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ा, विशेषकर सूखे या फसल की विफलता के दौरान। नकदी फसलों पर जोर देने से स्थानीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई, जिससे आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भरता बढ़ गई। ग्रामीण आजीविका के संदर्भ में, नकदी फसल की खेती को बढ़ावा देने का मिश्रित प्रभाव पड़ा। जबकि कुछ किसान औपनिवेशिक बाजार में नकदी फसलों की ऊंची कीमतों से लाभ उठाने में सक्षम थे, वहीं कई अन्य को नई कृषि व्यवस्था को अपनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नकदी फसलों की खेती के लिए अक्सर बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे इनपुट में अधिक वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे पहले से ही गरीब किसान परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके अलावा, नकदी फसलों की कीमतों में उतार–चढ़ाव ने किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं और जोखिमों के अधीन कर दिया, जिससे उनकी आर्थिक असुरक्षा और बढ़ गई।

आर्थिक दृष्टिकोण से, निर्यात बाजारों के लिए वाणिज्यिक कृषि पर जोर देने का रोहिलखंड की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जबकि नकदी फसल की खेती से जमींदारों और औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए राजस्व उत्पन्न हुआ, इसने छोटे पैमाने के किसानों और पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को हाशिए पर धकेलने में योगदान दिया। वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था में रोहिलखंड के एकीकरण ने इसे बाहरी झटकों और व्यवधानों के प्रति भी संवेदनशील बना दिया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों में बदलाव या वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उतार–चढ़ाव। ब्रिटिश शासन के तहत रोहिलखंड में नकदी फसल की खेती की ओर बदलाव के पारंपरिक कृषि पद्धतियों, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम हुए। हालाँकि इसने औपनिवेशिक अधिकारियों और जमींदारों के लिए राजस्व सृजन में योगदान दिया, इसने ग्रामीण आबादी के बीच गरीबी, खाद्य असुरक्षा और आर्थिक भेद्यता को भी बढ़ा दिया। यह औपनिवेशिक काल के दौरान रोहिलखंड की कृषि अर्थव्यवस्था और समाज पर ब्रिटिश नीतियों के जटिल और अक्सर हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डालता है।

औद्योगिक विकास

रोहिलखंड में पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प की गिरावट का श्रेय ब्रिटिश नीतियों को दिया जा सकता है, जो स्वदेशी उत्पादों की तुलना में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देती थीं। इस बदलाव का क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों और सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। टैरिफ, व्यापार नियमों और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के प्रचार सहित ब्रिटिश नीतियों ने रोहिलखंड में पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर दिया। उदाहरण के लिए, आयातित ब्रिटिश वस्त्रों ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी, जिससे स्थानीय कपड़ा उत्पादकों और कारीगरों को नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर कर और शुल्क लगा दिए, जिससे स्वदेशी उद्योगों को और नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप, रोहिलखंड में कई पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प में उत्पादन, मांग और लाभप्रदता में गिरावट का अनुभव हुआ। कारीगर और श्रमिक जो पहले बुनाई, मिट्टी के बर्तन, धातु के काम और चमड़े के काम जैसे शिल्प में लगे हुए थे, उन्होंने खुद को हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर पाया। इससे कारीगर समुदायों के भीतर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक अव्यवस्था पैदा हुई।

रोहिलखंड में ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना ने स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रों की गिरावट को और बढ़ा दिया। औपनिवेशिक नीतियों और पूंजी द्वारा समर्थित ब्रिटिश उद्यमियों ने कारखानों और विनिर्माण उद्यमों की स्थापना की जो सीधे पारंपरिक भारतीय उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। ब्रिटिश स्वामित्व वाले इन उद्योगों को अक्सर तरजीही व्यवहार, ऋण तक पहुंच और तकनीकी प्रगति से लाभ हुआ, जिससे उन्हें स्वदेशी उत्पादकों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली।

रोहिलखंड में ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों की आमद का स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों पर कई प्रभाव पड़ा। सबसे पहले, इससे पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों का विस्थापन हुआ, जिनमें से कई ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्यमों के पैमाने, दक्षता और संसाधनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में पारंपरिक शिल्प कौशल और कौशल का और अधिक क्षरण हुआ। ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना ने रोहिलखंड में औद्योगिक पूंजीपतियों और उद्यमियों का एक नया वर्ग तैयार किया, जो अक्सर स्थानीय अभिजात वर्ग या ब्रिटिश के सहयोगियों से आते थे। इन व्यक्तियों को औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ अपने संबंधों और बाजारों, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच से लाभ हुआ, जिससे समाज के भीतर आर्थिक असमानताएं और बढ़ गईं।

जबकि ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों ने आबादी के कुछ हिस्सों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए, खासकर शहरी क्षेत्रों में, श्रम की स्थितियाँ अक्सर शोषणकारी और दमनकारी थीं। ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्टरियों में श्रमिकों को लंबे समय तक काम करने, कम वेतन, असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और सीमित अधिकारों या सुरक्षा का सामना करना पड़ा। श्रम के इस शोषण ने रोहिलखंड में श्रमिक वर्ग के बीच सामाजिक अशांति और प्रतिरोध आंदोलनों में योगदान दिया। ब्रिटिश नीतियों और ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना के कारण रोहिलखंड में पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प की गिरावट का क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे स्वदेशी उत्पादक हाशिए पर चले गए, आर्थिक शक्ति ब्रिटिश उद्यमियों के हाथों में केंद्रित हो गई और श्रम का शोषण होने

लगा। ये घटनाक्रम औपनिवेशिक काल के दौरान रोहिलखंड की औद्योगिक अर्थव्यवस्था और समाज पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हानिकारक प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

कराधान और व्यापार नीतियां

रोहिलखंड में व्यापार और वाणिज्य पर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा कर, शुल्क और टैरिफ लगाने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, स्थानीय व्यापारियों, व्यापारियों और समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का उद्देश्य राजस्व निष्कर्षण को अधिकतम करना और ब्रिटिश आर्थिक हितों को बढ़ावा देना था, अक्सर रोहिलखंड में स्वदेशी व्यापारियों और व्यापारियों की कीमत पर। आयात, निर्यात और अंतर–क्षेत्रीय व्यापार सहित विभिन्न वस्तुओं और लेनदेन पर कर, शुल्क और टैरिफ लगाए गए थे। इन औपनिवेशिक थोपने से कई उद्देश्य पूरे हुए, जिनमें राजस्व सृजन, ब्रिटिश उद्योगों की सुरक्षा और भारतीय बाजारों पर नियंत्रण शामिल था। रोहिलखंड में स्थानीय व्यापारियों और व्यापारियों पर ब्रिटिश व्यापार नीतियों का प्रभाव दोहरा था। सबसे पहले, करों और शुल्कों को लगाने से व्यापार के संचालन की लागत में वृद्धि हुई, जिससे स्वदेशी व्यापारियों के लिए ब्रिटिश व्यापारियों और व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना अधिक कठिन हो गया, जिन्हें तरजीही उपचार और छूट प्राप्त थी। इससे स्वदेशी वाणिज्यिक उद्यमों के विकास में बाधा उत्पन्न हुई और स्थानीय व्यापारियों के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर सीमित हो गए।

ब्रिटिश व्यापार नीतियां अक्सर स्वदेशी उत्पादों की तुलना में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देती थीं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को और अधिक नुकसान होता था। ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर उच्च टैरिफ लगाया गया, जबकि ब्रिटिश निर्मित सामानों को भारतीय बाजारों में तरजीह दी गई। इस विषम व्यापार संबंध ने भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर दिया, जिससे स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं की मांग में गिरावट आई। रोहिलखंड की समग्र अर्थव्यवस्था ब्रिटिश व्यापार नीतियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र के वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के ठहराव और अविकसितता में योगदान दिया। करों और टैरिफों को लागू करने से आर्थिक बाधाएँ पैदा हुईं जिससे व्यापार और वाणिज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हुई, आर्थिक अवसर और नवाचार बाधित हुए। इसके अलावा, ब्रिटेन और भारत के बीच असमान व्यापार संबंधों के परिणामस्वरूप रोहिलखंड से धन ब्रिटिश खजाने में चला गया, जिससे यह क्षेत्र और अधिक गरीब हो गया।

ब्रिटिश व्यापार नीतियों का रोहिलखंड के लिए व्यापक सामाजिक–आर्थिक प्रभाव था, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और उनके सहयोगियों के हाथों में आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण भी शामिल था। औपनिवेशिक नीतियों और संसाधनों द्वारा समर्थित ब्रिटिश व्यापारियों और व्यापारियों ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, जिससे स्वदेशी उद्यमियों को हाशिये पर धकेल दिया गया और आर्थिक असमानताएँ बढ़ गईं। रोहिलखंड में व्यापार और वाणिज्य पर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा कर, शुल्क और टैरिफ लगाने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, स्थानीय व्यापारियों, व्यापारियों और समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। इन नीतियों ने ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को मजबूत किया, स्वदेशी

वाणिज्यिक उद्यमों के विकास में बाधा डाली और औपनिवेशिक काल के दौरान रोहिलखंड के आर्थिक शोषण और अविकसितता में योगदान दिया।

आर्थिक शोषण

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा रोहिलखंड का आर्थिक शोषण ब्रिटिश शासन की एक केंद्रीय विशेषता थी, जो ब्रिटिश हितों के लाभ के लिए संसाधनों के व्यवस्थित निष्कर्षण, धन हस्तांतरण और आर्थिक प्रभुत्व की विशेषता थी। रोहिलखंड में अंग्रेजों द्वारा नियोजित आर्थिक शोषण का एक तंत्र राजस्व निष्कर्षण को अधिकतम करने के उद्देश्य से निष्कासन आर्थिक नीतियों को लागू करना था। इसमें भूमि राजस्व, व्यापार और वाणिज्य जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर भारी कर, शुल्क और टैरिफ लगाना शामिल था। ये कर अक्सर मनमाने और अत्यधिक होते थे, जिससे स्थानीय आबादी पर बोझ पड़ता था और संसाधनों को स्वदेशी आर्थिक गतिविधियों से ब्रिटिश खजाने में स्थानांतरित कर दिया जाता था।

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने ऐसी नीतियां लागू कीं जो रोहिलखंड में स्वदेशी उद्यमों की तुलना में ब्रिटिश उद्योगों और उत्पादों को प्राथमिकता देती थीं। इसमें भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए तरजीही व्यवहार, ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर उच्च शुल्क और स्वदेशी औद्योगिक विकास पर प्रतिबंध शामिल थे। परिणामस्वरूप, रोहिलखंड ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बंधक बाजार बन गया, जबकि स्वदेशी उद्योगों को औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के बोझ तले प्रतिस्पर्धा करने और जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रोहिलखंड में ब्रिटिश आर्थिक शोषण का एक अन्य प्रमुख पहलू संसाधन निष्कर्षण था। क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे भूमि, खनिज, वन और जलमार्ग, का ब्रिटिश हितों के लिए शोषण किया गया, अक्सर स्थानीय आबादी के कल्याण या पर्यावरणीय स्थिरता की परवाह किए बिना। नकदी फसल की खेती और ब्रिटिश स्वामित्व वाले बागानों के लिए भूमि का विनियोग किया गया, किसानों को विस्थापित किया गया और पारंपरिक आजीविका को बाधित किया गया। लकड़ी के निष्कर्षण और व्यावसायिक दोहन के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया, जिससे स्थानीय समुदाय निर्वाह और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित हो गए।

रोहिलखंड से ब्रिटेन में धन हस्तांतरण को धन की निकासी, असमान व्यापार संबंधों और ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा मुनाफे के प्रत्यावर्तन जैसे तंत्रों के माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया था। रोहिलखंड की अर्थव्यवस्था से उत्पन्न अधिशेष, जिसमें कृषि उपज, कच्चा माल और श्रम शामिल था, ब्रिटिश हाथों में चला गया, जिससे स्थानीय आबादी की कीमत पर औपनिवेशिक प्रशासकों, ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों को समृद्ध किया गया। रोहिलखंड में अंग्रेजों द्वारा आर्थिक प्रभुत्व को कानूनी ढांचे, प्रशासनिक संरचनाओं और सैन्य शक्ति सहित विभिन्न माध्यमों से लागू किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों और विनियमों ने ब्रिटिश हितों का समर्थन किया और औपनिवेशिक प्रशासकों और सहयोगियों के विशेषाधिकारों की रक्षा की। औपनिवेशिक राज्य के प्रशासनिक तंत्र ने शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखना सुनिश्चित किया। इसके अलावा, रोहिलखंड में ब्रिटिश सैन्य बलों की उपस्थिति ने औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने और आर्थिक शोषण के प्रतिरोध को दबाने का काम किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा रोहिलखंड के आर्थिक शोषण की विशेषता ब्रिटिश हितों के लाभ के लिए

संसाधनों का व्यवस्थित निष्कर्षण, धन हस्तांतरण और आर्थिक वर्चस्व था। निष्कर्षण आर्थिक नीतियों, संसाधन निष्कर्षण, धन हस्तांतरण तंत्र और आर्थिक वर्चस्व के माध्यम से, ब्रिटिशों ने स्थानीय आबादी की कीमत पर खुद को समृद्ध किया, जिससे औपनिवेशिक काल के दौरान रोहिलखंड में आर्थिक असमानता और अविकसितता बनी रही।

उपसंहार

यह अध्ययन लेख वर्ष 1857 तक रोहिलखंड पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश प्रदान करके समाप्त होता है। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा लाए गए भारी आर्थिक परिवर्तनों पर जोर देता है और निरंतर परिणामों को दर्शाता है। इन नीतियों ने क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव डाला है। इसके अलावा, यह उन पिछली आर्थिक ताकतों को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है जिन्होंने रोहिलखंड और उससे आगे आधुनिक वास्तविकता को परिभाषित करने में भूमिका निभाई है।

संदर्भ

1. अली, एम. (2015) समाज के सबसे गरीब तबके का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण – भिखारीरू उत्तर प्रदेश, भारत का एक केस स्टडी, पृष्ठ संख्या13.

2. अनूप कुमार शुक्ला, सी. एस. (2018) जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग और भूमि आवरण परिवर्तन, और ऊपरी गंगा नदी बेसिन में जल गुणवत्ता संबंध। जल विज्ञान. पृथ्वी प्रणाली. विज्ञान , पृष्ठ संख्या 22.

3. अशोक गुलाटी, पी. टी. (2016), उत्तर प्रदेश में कृषि का प्रदर्शन, पृष्ठ संख्या 209–215

4. गेडेस, ए. (2014) सिन्धु–गंगा के मैदान की जलोढ़ आकृति विज्ञानरू इसका मानचित्रण और भौगोलिक महत्व। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता संस्थान, , पृष्ठ संख्या 253–276 मानचित्र तैयार करने के लिए– ीजजचेरूध्ध् कंजूंतंचचमत.कमध्।

5. जे. वेंकेटेश्वरालु, वाई. आर. (1996) भारत में कृषि–जलवायु क्षेत्र शुष्क क्षेत्र का इतिहास, , पृष्ठ संख्या 7.

6. खान, आर. एच. (2018) उत्तर प्रदेश, भारत में कृषि उत्पादन और उसके प्रदर्शन का अस्थायी विश्लेषण, करंट माइक्रोबायोलॉजी और एप्लाइड साइंसेज के इंटरनेशनल जर्नल, , पृष्ठ संख्या 06.

7. मोहम्मद मोनिरुल इस्लाम, एम.एम. (2014) ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक–आर्थिक स्थितिरू एक आय स्तर विश्लेषण, एशियन एकेडेमिक रिसर्च जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, , पृष्ठ संख्या 10.

8. महक रतन, जी.एस. (2021) भारत–गंगा के मैदानों में भूमि उपयोग का इतिहास, भारत और इसका प्रभाव। प्लांट अभिलेखागार, , पृष्ठ संख्या 532–537।

9. एन.एल. कालरा, एस.के. (1997) एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस की व्यापकता–उत्तर, उत्तर–पूर्व और मध्य भारत में डेंगू और डेंगू रक्तस्रावी बुखार के वाहक, डेंगू बुलेटिन, , पृष्ठ संख्या 21.

10. अनंतिम जनसंख्या योग – उत्तर प्रदेश ग्रामीण – शहरी वितरण, (2011) भारत की जनगणना.

11. रहमान, ए. (2004) उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में कृषि के सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका, पृष्ठ संख्या 67

12. श्रीवास्तव, वी.के. (1988) दक्षिण एशिया में वाणिज्यिक गतिविधियाँ और ग्रामीण विकासरू एक भौगोलिक वी.के. श्रीवास्तव में, दक्षिण एशिया में वाणिज्यिक गतिविधियाँ और ग्रामीण विकासरू एक भौगोलिक , पृष्ठ संख्या 496, भारतरू कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी।

13. सिंह, आर. (1971) भारतरू एक क्षेत्रीय भूगोल. (आर. सिंह, एड.) वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारतरू नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, पृष्ठ संख्या 90।

14. सिंह, एस. (2019) उत्तर प्रदेश, भारत में कृषि उत्पादन के निर्धारकरू एक क्षेत्रीय विश्लेषण, रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, पृष्ठ संख्या 11।

15. त्रिपाठी, ए. (2014)। सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता हैरू उत्तर प्रदेश से साक्ष्य , पृष्ठ संख्या 45.

16. वी.के. भाटिया, एस.आर. (2003–04) छोटे क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास का मूल्यांकन, आईएएसआरआई परिसर, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्लीरू भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी, पृष्ठ संख्या 291।